

जात हो कि फूटप्लेट निरीक्षण में रेल अधिकारी ट्रेन के ड्रजन में लोको पायलेंट के साथ यात्रा करते हैं। बुधवार के निरीक्षण में महाप्रबंधक ने लोकोपायलेंट के संचालन और संरक्षा प्रक्रियाओं का सूक्ष्मतत्पुर्वक अवलोकन किया। इसी दौरान उन्होंने गार्म के विमलन और अन्य परिचालनक इन्टेलोजन का भी जाण्यल किया। महाप्रबंधक ने लोको पायलेंटों से रेल परिचालन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में महाप्रबंधक ने कानपुर अनवरगंज स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने यार्ड सूविधाओं, परिचालन व्यवस्थाओं, कर्मचारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक बैठक में मैनेजर्स की विभिन्न यूनित का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

» दखल अवैध खनन पर लगाम जरूरी



एनजीटी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात क्षेत्र के 548 वर्ग किलोमीटर में खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। अरावली की हरियाली लौटाने की दृष्टि से न्यायाधिकरण ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को कहा था और साथ ही क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और खनन माफिया के दबदबे से ये दोनों ही काम नहीं हो पाए और अवैध खनन आज भी जारी है।

» राज-विचार पीओके पर पाक को कड़ा संदेश

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कहा कि यह हिस्सा भारत का है और रहेगा। कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आक्रामकता सही दिशा में है। जब तक भारत इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में पाक को नहीं धेरेंगा, तब तक वह सुधरने वाला नहीं है।



रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जम्मू से हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। पूरा देश इस तथ्य पर एकमत है, संसद में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, बावजूद उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। सिंह ने आगे कहा कि भगवान शिव का हिमस्वरूप हमारे पास है और मां शारदा पीठ आज भी नियंत्रण रखा के उस पार हैं, ऐसा क्यों है? राजनाथ ने विशावास दिलाया कि आज नहीं तो कल हमारी यह मन्नत भी पूरी होगी। कश्मीर के मुद्दे पर रक्षामंत्री ने जिस तरह का रुख दिखाया है, वैसी आक्रामकता जरूरी है, क्योंकि पाक जब-तब वैश्विक मंचों पर कश्मीर काई खेलने में लगा है। इसलिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। भारत ने गुलाम कश्मीर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को कई मर्ताब इसे खाली करने की चेतावनी दी है। किंतु उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती।

मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर साबित किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है, बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह वहां रह रहे नागरिकों का शोषण और दमन है। इस दमन की तस्वीरें वीडियो से सामने आती रही हैं। पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान और ब्लूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब एवं लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, वहीं ब्लूचिस्तान की भूमि से खनिज तथा तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए हैं। नतीजतन यहां खेती-किसानी, उद्योग-धंधे, शिक्षा-रोजगार और स्वास्थ्य-सुविधाएं तथा पर्यटन सब चौपट है।

दरअसल कश्मीर की समस्या आज की देन नहीं हैं। 1948 में कांग्रेस और नेशनल फ्रांफ्रेंस की कारगुजारियों के चलते यहां बढ़हाली आज तक कायम है। कश्मीर के ये हालात इसलिए भी उत्पन्न हुए, क्योंकि यहां शुरुआत में लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया। शेख अब्दुल्ला को राज्य का बड़ा नेता होने के कारण सीधे प्रधानमंत्री बना दिया गया। यदि स्थानीय नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए राज्य का प्रधानमंत्री चुनने का मौका दिया होता तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा पुख्ता होता। हालांकि अब धारा-370 एवं 35-ए हटने के बाद कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं, इसी का परिणाम है कि इस बार घाटी में सात लाख से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं, जो जनता की आर्थिक बहाली का कारण बन रहे हैं। कश्मीर में दिन-प्रतिदिन जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, उससे लगता है कि हमें पीओके जल्द मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग पाक के खिलाफ मोर्चा बुलंद करेंगे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एनबी रमना और सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में पड़े विचाराधीन कैदियों की ओर देश का ध्यान खींचा है तथा एक ऐसे मुद्दे को सामने रखा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है, नागरिकों की आजादी छिनती है और अधिकतर जांचों में जमानत देने की जगह जेल भेजना कायदा बनता जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश ने एक संबोधन में रेखांकित किया कि हमारे देश में जेलों में बंद 6.10 लाख नागरिकों में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में प्रक्रिया ही दंड बन गई है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों से लेकर जमानत मिलने में मुश्किलों तक की इस प्रक्रिया में लंबे समय तक जेलों में बंद लोगों के इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कैदी ब्लैक बाॅक्स की तरह हैं। वे ऐसे नागरिक हैं, जिन्हें अनदेखा और अनसुना कर दिया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे मुद्दे को उठाया है, जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कोई हाल में आई अस्थायी गिरावट नहीं है, बल्कि भारतीय व्यवस्था की स्थायी विशेषता बन चुकी है।

सजा दिलाने लंबी जांच की बजाय तुरंत हिरासत में लेने के रवैये से भी न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जमानत की अर्जियों की तादाद बहुत अधिक है। चूँकि हिरासत में लेना आम बात है, तो अग्रिम जमानत के लिए भी बहुत सारे लोग अदालत पहुंचते हैं। इनसे बड़ी अदालतों में बोझ बढ़ता जाता है। इन सबसे ऐसी व्यवस्थागत समस्या पैदा हो गई है, जिसका समाधान जजों की संख्या बढ़ाकर नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे यहां अभियुक्तों को सजा देने की दर बहुत ही कम है। ऐसे में ठोस जांच दर्कनार कर दी जाती है और मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना ही सजा बना दिया जाता है। इससे न्याय व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत, जिसमें दोष सिद्ध होने तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है, ही खारिज हो जाता है।

इस माह की 11 तारीख को अपने 85 पन्ने के आदेश में न्यायाधीश एसके कौल व एमएम सुंदरेश ने समस्या के व्यवस्थागत प्रकृति की ओर संकेत किया है-अदालतें सोचती हैं कि चूँकि सजा होने की संभावना बहुत ही कम है, तो जमानत की अर्जियों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हम जमानत पर विचार करते हुए बहुत सी बातों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसका दंड से लेना-देना नहीं है। अगर कोई लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बरी हो जाता है, तो वह बेहद गंभीर अन्याय है। कामकाज का कोई लेना-देना राजनीति या



यह पहली बार नहीं है कि जेलों में बंद आरोपियों के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो। 2010 में राष्ट्रीय विधिक अभियान के तहत भी विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने का बीड़ा उठाया गया था। पर धरातल पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सजा दिलाने लंबी जांच की बजाय तुरंत हिरासत में लेने के रवैये से भी न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जमानत की अर्जियों की तादाद बहुत अधिक है।

नेताओं या एजेंडे से नहीं होता। व्यवस्था का हर जगह होना उसका संन्त्रास है। वह हवा व पानी में घुल-मिल जाता है तथा बहुत से लोगों को जेल में डालकर उनमें से कुछ सबसे कमजोर नागरिकों को भूल जाता है। इससे कैसे व्यवस्था की रीढ़ टूटती है, हम उसे आसानी से या ठीक से नहीं समझते। एक तो यह बिना मुकदमे के सजा दे देता है, जिसके लिए सबूतों का संज्ञान लिया जाना चाहिए और हर तरह से परखने के बाद ही अभियुक्त को दोषी ठहराना चाहिए। राज्य ने एकदम बुनियादी स्तर पर और रोमरंग के काम में ऐसा कर न्यायिक व्यवस्था को खत्म भले न किया हो, पर उसे अप्रासंगिक जरूर कर दिया है। यह सब न्यायपालिका के सहयोग से ही हुआ है, जहां लगातार हिरासत में रखने के फैसले दिये जाते हैं और जमानत पाना मुश्किल होता है क्योंकि मामले के बारे में अक्सर न तो ठीक से विचार किया जाता है और कई बार तो उसके बारे में पूछा भी नहीं जाता। अगर हिरासत

में रखने की अनुमति चलन बन जाए, तो पुलिस जजों को लेकर निश्चित हो जाती है और इसका सीधा व तुरंत असर जांच की गुणवत्ता पर पड़ता है। न्यायाधीश कौल और सुंदरेश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए एक निर्णय को उद्धृत करते हुए लिखा कि हमारे इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिसकर्मी अभियुक्त को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करें और मजिस्ट्रेट लापरवाही से एवं यात्रिक तौर से उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश न पारित करें। वे आगे लिखते हैं, हिरासत में रखने का आदेश देने का अधिकार गंभीर दायित्व है। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है तथा इस अधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

हमारा अनुभव हमें बताता है कि इस अधिकार का प्रयोग उस गंभीरता से नहीं किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में हिरासत में रखने का आदेश नियमित, लापरवाही भरा और

बिना सोचे दिया जाता है। असल में, हिरासत का आदेश इतना सामान्य हो गया है कि पुलिस अधिकारी समुचित या पूरा विवरण भी पेश करने की जहमत नहीं उठाते। कभी-कभी इससे जांच एजेंसियों में घमंड भी भर जाता है कि कुछ भी चल सकता है। इससे जांच के शुरुआती चरण में ही मामला भटक जाता है, जबकि इस अहम मोड़ पर बहुत सावधानी बरतने और समयबद्ध होकर काम करने की जरूरत होती है। ऐसा होने से हिरासत में होने वाली हिराा के मामले से भी पुलिस का बचाव हो जाता है। कानूनी प्रावधानों के बावजूद यह समस्या भी गंभीर होती जा रही है।

इसलिए यह कोई अचानक नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से जमानत पर एक कानून बनाने को कहा है। न्यायाधीश कौल और सुंदरेश ने रेखांकित किया है, हम सरकार से अग्रह करते हैं कि वह ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में बने कानूनों की तरह जमानत देने के बारे में विशेष कानून लाने पर विचार करें। निश्चित ही उल्लेखनीय पहल होगी। वैधानिक व्यवस्था में विशेष दिशा-निर्देशों को रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी समस्या औपनिवेशिक मानसिकता की है, जो अभी भी भारतीय नौकरशाही पर हावी है। इसके साथ ही अच्छे करने वाले लोगों के सहयोग के लिए निवेश की कमी तथा व्यवस्था के साथ हेर-फेर करने वालों को सजा देने का अभाव जैसी समस्याएं भी हैं। यहां पर अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए। शुरू से ही मामलों की निगरानी होनी चाहिए और जांच एजेंसियों की मांग की समीक्षा होनी चाहिए।

ऐसा करने से हमारी जांच व्यवस्था की कई खामियां दूर हो सकेंगी और एजेंसियां अधिक उत्तरदायी होंगी। साथ ही, इससे पुलिस सतर्क रहेगी और जेलों में भीड़ कम होगी तथा पूरी व्यवस्था के प्रभाव में बेहतर होगी। उच्चतम न्यायालय ने साल 2014 में व्यवस्था दी थी कि उन विचाराधीन आरोपियों को तुरंत जमानत पर रित किया जाए जिन्होंने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक कारावास पर जाकर इस प्रकार के कैदियों की रिहाई के लिए आवश्यक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इन आदेशों के बाद लंबी अवधि से जेलों में बंद विचाराधीन कैदी रिहा हो सकेंगे।

■ **जगदीश रत्नानी**
(वरिष्ठ पत्रकार)

विकास की निरंतरता तो बनी नहीं रह सकती, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से देखे तो विकास की यह आवश्यकता उस बहुसंख्यक आबादी के लिए जीने का भयावह संकट खड़ा कर सकती है, जिसकी रेजी-गेटी की निर्भरता ही प्रकृति पर अवलंबित है। इसी खतरे को भांपते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से उत्खनन पर प्रतिबंधित लगा दिया था। लेकिन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से इस पर अमल में लापरवाही बरती जा रही है।

नतीजतन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने एक बार फिर इन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं को बचाने के लिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पूरे अरावली क्षेत्र में सड़क निर्माण और पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से यह संदेश गया था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन नूंह की घटना बता रही है कि अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी रहा। सवाल है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आज सीमेंट, कंक्रीट व लोहे की संरचनाओं से जुड़ा आधुनिक विकास हो अथवा कंप्यूटर व संचार क्रांति से संबंधित प्रौद्योगिक विकास, सबकी निर्भरता प्राकृतिक संपदा पर ही है। इस विकास की बुनियाद जल, जंगल और जमीन पर तो टिकी है ही, खनिज, जीवाश्म ईंधन, रेडियोधर्मी और तलत पदार्थ भी विकास के अपरिहार्य पहलू बन चुके हैं। हालांकि ये खनिज संपदाएं अब अकूत नहीं रहीं। बेशुमार दोहन से इनके भंडार भी तेजी से घट रहे हैं। लिहाजा प्रकृति के समक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का संकट गहराने के साथ बड़ी आबादी के जीने का अधिकार भी खतरे में पड़ता जा रहा है। क्योंकि प्रकृति के खजाने लूट लिए जाएंगे तो जीने के अधिकार के प्रावधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

एनजीटी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद व मेवात क्षेत्र के 548 वर्ग किमी में खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। अरावली की हरियाली लौटाने की दृष्टि से न्यायाधिकरण ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को कहा था और साथ ही क्षेत्र में कचरा फेंकने पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और खनन माफिया के दबदबे से ये दोनों ही काम नहीं हो पाए और अवैध खनन आज भी जारी है। गौरतलब है कि अरावली की पहाड़ियां दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से हैं। लगभग आठ सौ किलोमीटर के दायरे में फैली ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हैं। मानव समुदाय के लिए इन पहाड़ियों का कुदरती महत्व है। इनकी

ओट ही पश्चिमी रेगिस्तान को फैलने से रोके हुए है, वरना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है, उसे रेगिस्तान में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा।

अवैध खनन सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में भी उत्खनन की जारी रहने से वन क्षेत्रों और नदियों की गहराई पर असर पड़ रहा है। पश्चिम के ये वन प्रांत दुर्लभ वनस्पतियों और जैव विविधता के अनुपम उदाहरण हैं। यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए भी सर्वोच्च न्यायलय को पहल करनी पड़ी थी। मध्य क्षेत्र में भी प्राकृतिक संपदाओं के बेहताशा दोहन से सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रेंगियां और कई नदियों का वजुद संकट में है। छत्तीसगढ़ में कच्चे अयस्क के अति दोहन ने शांखनी नदी को प्रदूषित कर डाला है। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगे इस्पात संयंत्र रेजाना करीब साठ टन दूषित मलवा चंबल और चामला नदियों में बहा कर उन्हें दूषित बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र को गड़बड़ाने वाली रेणुका बांध परियोजना को रद्द करने की भी मांग उठ रही है। इस परियोजना को अस्तित्व में लाने का मुख्य मकसद दिल्लीवासियों को अतिरिक्त 27 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन मुहैया कराना है।

वर्ष 1994 की इस परियोजना पर पांच सहयोगी प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तर प्रदेश समझौता करने एकजुट हुए थे। लेकिन राजस्थान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में परियोजना रद्द मानी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना जारी रहती है तो निचले हिमालय क्षेत्र में दो हजार हेक्टेयर में फैले जंगल और कृषि क्षेत्र डूब जाएंगे। संकट इसलिए गहराता जा रहा है कि हम विकास का ऐसा आदर्श और संतुलित रूप तैयार करने में नाकाम रहे हैं जिसमें विकास की गतिशीलता भी बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी धक्का न पहुंचे। आधुनिक विकास का आधार प्राकृतिक संसाधन हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे नीतिगत उपाय करती हैं, जिससे हर प्रकार के निर्माण कार्यों में कोई अड़चन न आए। खासतौर से भवन और सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल खनन सामग्री का होता है। इस्पात की भी इसमें बड़ी खपत होती है।

■ **प्रमोद भार्गव**
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचाराधीन कैदी और लोकतंत्र

दिवटर

अब भारत कमजोर देश नहीं बल्कि शक्तिशाली राष्ट्र है। उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करने का कोई साहस नहीं दिखा सकता। यदि युद्ध हुआ तो भारत की जीत होगी।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

आतंकवाद शांति और विकास के साझा लक्ष्य का बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान आतंकवाद को पीओके में पाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बुगई के खिलाफ एकजुट हो।

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

राजा ययाति और देवयानी पति-पत्नी थे। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। जब इनका विवाह हुआ था दैत्यों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ दासी के रूप में गई थी। दरअसल शर्मिष्ठा देवयानी से एक शरत हर गई थी और इस कारण उसे देवयानी की दासी बनना पड़ा था। उस समय शुक्राचार्य ने ययाति से एक वचन लिया था कि वह कभी भी देवयानी के अलावा किसी अन्य स्त्री से रिश्ता नहीं रखेगा। ययाति ने भी शुक्राचार्य को ये वचन दे दिया था। कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती हो गई।

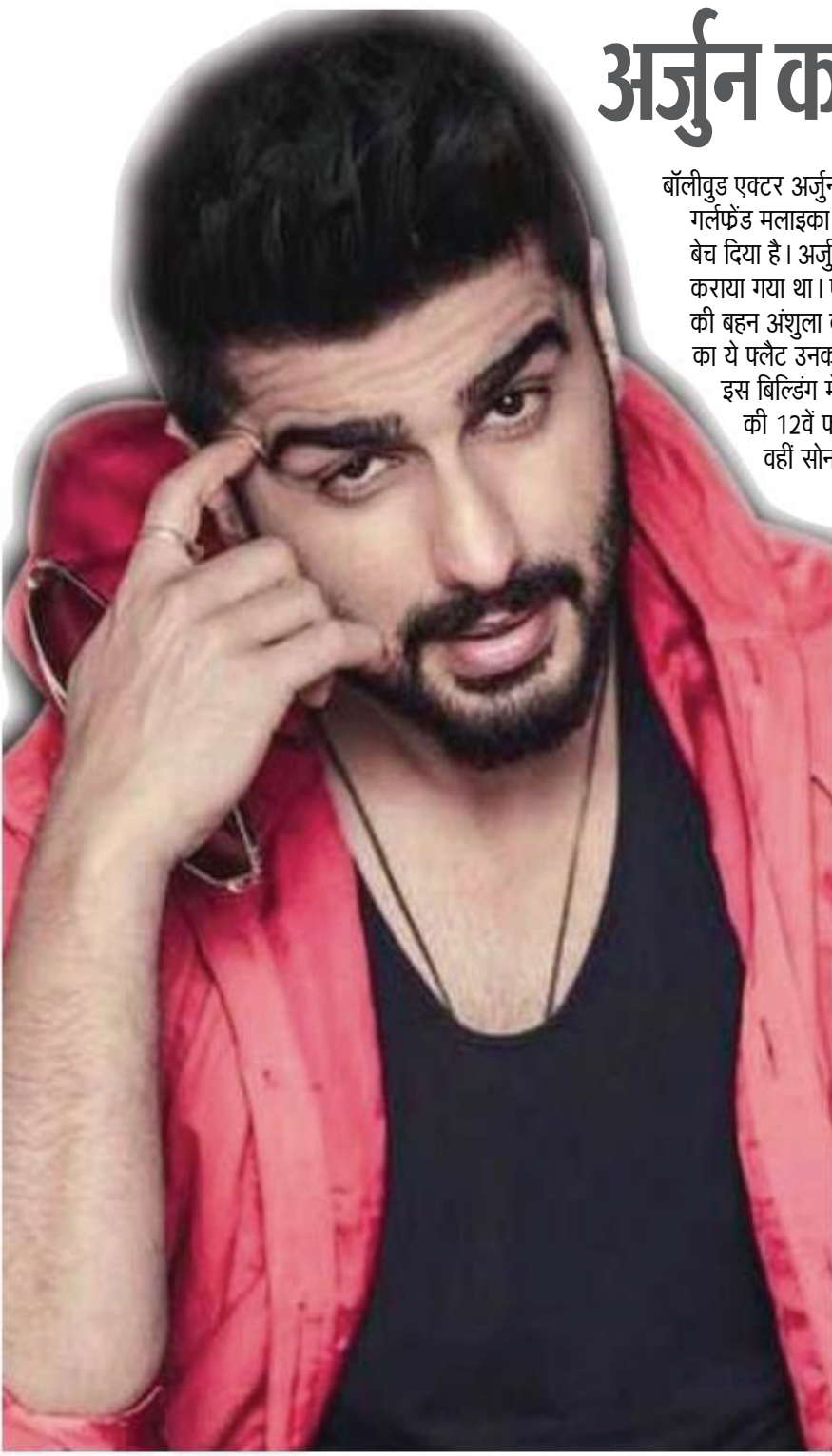
दूसरी ओर शर्मिष्ठा एक दासी के रूप में ययाति के महल के पीछे छोटी सी कुटिया में रह रही थी। एक दिन ययाति शर्मिष्ठा को देखकर उसकी ओर मोहित हो गए और उन्होंने शर्मिष्ठा से संबंध बना लिए। राजा ययाति शुक्राचार्य को दिया हुआ वचन भी भूल गए थे। बाद में शर्मिष्ठा और ययाति की बात जब देवयानी को मालूम हुई तो वह अपने पिता के घर पहुंच गई और पूरी बात बता दी। शुक्राचार्य इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ययाति को शाप दे दिया कि वे तुरंत बूढ़े हो जाएंगे। शाप के असर से ययाति

बूढ़े हो गए। इस तरह देवयानी और ययाति का वैवाहिक रिश्ता बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। इस कथा की सीख यही है कि पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखें, साथ ही कभी भी एक-दूसरे का भरोसा न तोड़ें। वैवाहिक जीवन में भरोसा टूटना है तो रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल के साथ ही विश्वास न हो तो रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। श्रीमद्भागवत ग्रंथ में राजा ययाति और देवयानी की कथा से ये बात समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पति या पत्नी दोनों एक-दूसरे से कुछ न छिपाएं। अगर ऐसा होगा तो जीवन में तनाव बढ़ेगा।

मुकेश कुमार

अर्जुन कपूर ने बेची 16 करोड़ की प्रॉपर्टी

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपने बांद्रा वाले फ्लैट को 16 करोड़ में बेच दिया है। उन्होंने पिछले साल ही अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग में इस फ्लैट को 20 करोड़ में खरीदा था। लेकिन अब उन्होंने इसे 4 करोड़ के घाटे में बेच दिया है। अर्जुन का ये फ्लैट 4क़्राच है, जो 4364 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। सेल डॉक्यूमेंट को 19 मई को रजिस्टर कराया गया था। फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 96 लाख रुपए की स्टॉप ड्यूटी का पेमेंट किया गया है। वहीं अर्जुन की बहन अंशुला कपूर ने सेल्स डोक्यूमेंट पर साइन किया है। यह फ्लैट बांद्रा वेस्ट स्थित 81 औरेंट बिल्डिंग में था। अर्जुन का ये फ्लैट उनकी प्राइमरी लोकेशन नहीं थी। वो इस समय जुहू स्थित रहेजा ऑर्चिड बिल्डिंग में रह रहे हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग में कई सेलेब्स भी रहते हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा, करण कुंद्रा, आदि। करण कुंद्रा ने हाल ही में इस बिल्डिंग की 12वें फ्लोर पर 14 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदा है। उन्हें भी सबकी तरह 3 कार पार्क करने का एक्सेस मिला है। वहीं सोनाक्षी ने 2020 में यहां 16वें फ्लोर पर घर खरीदा था।



‘शमशेरा’ के डायरेक्टर ने संजय दत्त को बताया सुपरमैन

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘शमशेरा’ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म में संजय के रोल के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस समय संजय कैसर से जंग लड़ रहे थे। लेकिन पूरी शूटिंग के दौरान उन्होंने कभी जहिर नहीं होने दिया कि वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। साथ ही करण ने उन्हें सुपरमैन भी कहा, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कैसर से जंग जीती है। करण ने कहा, ‘संजय सर को कैसर होने की खबर हम सभी के लिए एक बड़े शॉक की तरह थी। हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे और ऐसे काम कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो इसी वजह से हैं। उन्होंने इस पर जीत हासिल की है। वो सेट पर सभी के लिए इन्सपिरेशन हैं।’ बता दें संजय दत्त को अगस्त 2020 में स्ट्रेज 4 लंग कैसर का पता चला था।



‘द ग्रे मैन’ के प्रीमियर में धोती पहनकर पहुंचे धनुष

साउथ सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट ‘द ग्रे मैन’ के प्रमोशन को लेकर बिजी चल रहे हैं। हाल ही में ‘द ग्रे मैन’ का प्रीमियर मुंबई में रखा गया। यहां धनुष बिल्कुल ट्रेडिशनल अवतार व्हाइट शर्ट और धोती में नजर आए और इस फिल्म को देखने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स पहुंचे। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनुष विकी कौशल को गले लगाते नजर आए। बता दें कि, इससे पहले फिल्म ‘द ग्रे मैन’ का प्रीमियर लंदन में रखा गया था। जहां धनुष उनके दोनों बेटे लिंगा और यात्रा के साथ पहुंचे थे।



पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन करेंगे रकुल प्रीत सिंह के यूजिक वीडियो ‘माशूका’ को साउथ मार्केट्स में प्रेजेंट

जेजस्ट म्यूजिक के पहले पैन इंडिया सिंगल ‘माशूका’ को हर तरफ पसंद किया जा रहा है। इसके हिंदी वर्जन को सभी पॉप सॉन्ग फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। अब जबकि ‘माशूका’ हिंदी में रिलीज हो गई है, निर्माता तमिल और तेलुगु बाजार में गाने को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने घोषणा की है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन तमिल और तेलुगु बाजार में माशूका पेश करेंगे। इस बात की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर करते हुए निर्माताओं ने लिखा, दिन की सबसे एक्साइटिंग खबर आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। यह शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित है कि हमारे पास और कोई नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन 29 जुलाई को तेलुगु और तमिल में माशूका को लॉन्च कर रहे हैं। गाने में खूबसूरत रकुल प्रीत सिंह को पॉप क्वीन गॉडसे के रूप में पेश किया है, जो अपने लेंस के जरिए अपनी विविध, खूबसूरत और बली पॉप वर्ल्ड में ले जाती हैं। रकुल प्रीत सिंह देखने में एक दृष्टि की तरह दिखती हैं, उनकी आभा बहुत शक्तिशाली है और पूरे म्यूजिक वीडियो में उनकी एनर्जी देखने लायक है। ‘माशूका’ का म्यूजिक वीडियो एक बहुत ही अलग पॉप दुनिया का वादा करता है। सेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए रंग वाइब्रेंट हैं, जो वीडियो को ऐजी बनाता है। ‘माशूका’ सबसे बोल्ट और अलग गाना है जो बी-टाउन गर्ल-नेक्स्ट-डोर रकुल प्रीत सिंह को सैसी पॉप-क्वीन में बदल देता है। इस गाने को असीस कौर, आदित्य अयंगर और देवाश शर्मा ने गाया है।



अदनान सामी का नया गाना अलविदा हुआ रिलीज

फेमस सिंगर अदनान सामी ने बीते दिनों अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर ‘अलविदा’ लिख सभी को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी। हालांकि कुछ दिन बाद अदनान ने बताया कि उनका गाना ‘अलविदा’ रिलीज होने वाला है। अब अदनान सामी का यह नया गाना रिलीज हो गया है। 2 साल के अंतराल के बाद यह उनका पहला गाना है। अलविदा एक वाइब्रेंट ट्रैक है यह गाना दिल टूटे आशिकों के लिए एंथम साबित हो सकता है। बता दें कि अदनान सामी सिंगर के साथ-साथ म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर और पियानिस्ट हैं। वे हिन्दी और साउथ मूवीज के लिए इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक बनाते हैं और गाते हैं। अदनान सामी को संगीत की दुनिया में शानदार योगदान देने के लिए पद्मश्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

पठान फिल्म की प्रमोशन के लिए शाहरुख खान तैयार

फिल्म पठान के साथ शाहरुख खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के बादशाह अपनी पठान फिल्म से जबरदस्त वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शाहरुख सिद्धार्थ आनंद निर्देशित इस फिल्म में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगे। बता दें कि पठान 4 साल के अंतराल के बाद वापसी कर रही है और इसी को देखते हुए शाहरुख खान फिल्म के प्रमोशन का बड़े पैमाने पर प्रचार करने की योजना बना रहे हैं। पठान फिल्म को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान पूरी दुनिया में घूमेंगे। पठान फिल्म के करीबी सूत्र ने बताया कि शाहरुख खान फिल्म के प्रमोशन की बड़ी योजना बना रहे हैं। एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि शाहरुख खान अपने एक्शन-एंटरटेनर पठान की प्रमोशन के लिए दुनिया भर में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। सुपरस्टार अकेले ही अपने फिल्म का प्रचार करेंगे। फिलहाल, शाहरुख न्यूयॉर्क और लंदन में फिल्म के प्रचार के लिए चर्चा में हैं।

शाहरुख की आने वाली परियोजनाएं

2023 में शाहरुख खान की तीन फिल्में रिलीज होगी। जहां तक पठान का सवाल है, यह फिल्म 25 जनवरी, 2023 को बड़े पर्दे पर आने वाली है। पठान के बाद, शाहरुख निर्देशक एटली की फिल्म जवान में नयनतारा के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 2 जून, 2023 को रिलीज की जाएगी। अपनी आगामी फिल्म के बाद, शाहरुख खान डंकी में तापसी पन्नू के साथ दिखाई देंगे। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 2023 में तीन बड़ी फिल्मों के साथ, शाहरुख खान एक से अधिक तरीकों से अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।



एक्ट्रेस को टारगेट कर रहा बॉलीवुड माफिया

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। तनुश्री दत्ता ने इस पोस्ट में बताया है कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशान और टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा तनुश्री ने यह भी बताया है कि उन्हें बॉलीवुड माफिया, पॉलिटिकल सर्किट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स टारगेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे सुसाइड करने वाली नहीं हैं। तनुश्री दत्ता ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, ‘मुझे परेशान किया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। प्लीज कोई तो कुछ करो। पहले पिछले एक साल में मेरे बॉलीवुड के काम को तहस-नहस कर दिया गया और फिर नौकरानी मेरे पानी में दवाइयां और स्टैरॉइड्स मिलाया करती थी। जिसकी वजह से मुझे हर तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। इसके बाद जब मैं मई में उज्जैन गई तो मेरी गाड़ी के ब्रेक से दो बार छेड़छाड़ हुई और फिर मेरा ऐक्सिडेंट हुआ था। मैं मरते-मरते बची और 40 दिनों बाद मैं मुंबई लौट आई और नॉर्मल लाइफ और काम में लग गई। अब एक अजीब सा वाकिया मेरी बिल्डिंग में मेरे ही फ्लैट के सामने हुआ।’



मानवाधिकारों का सम्मान हो, श्रीलंका के लोगों की

आकांक्षाओं को सुना जाएः अमेरिकी राजदूत

कोलंबो। अमेरिकी राजदूत जुली चुंग ने बुधवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और उनसे कहा कि श्रीलंका की नयी सरकार को सुराशन को अपनाना चाहिए, मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने लोगों की आकांक्षाओं को सुनना चाहिए। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विक्रमसिंघे की हालिया कार्रवाई की आलोचना करने वाली चुंग ने विक्रमसिंघे से राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की।अमेरिकी राजदूत ने टवीट कर कहा, ‘‘राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ आज राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया है जब श्रीलंका एक ‘चौराहे’ पर खड़ा है। हमने चर्चा की कि यह (श्रीलंका) आर्थिक और राजनीतिक संकट के इस बिंदु पर कैसे पहुंचा और हम सभी लोगों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के वास्ते किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।’’ चुंग ने कहा कि दोनों देश और उनके लोग 70 से अधिक वर्षों से मित्र और भागीदार रहे हैं।

यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य आयुक्त ने

मंकीपॉक्स से निपटने के वास्ते कार्रवाई

तेज करने का आग्रह किया

ब्रसेल्स। स्वास्थ्य के लिए यूरोपीय संघ की आयुक्त ने क्षेत्र की सरकारों से मंकीपॉक्स से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज करने का बुधवार को आग्रह किया। यूरोपीय संघ के 27 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भेजे एक पत्र में, यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य आयुक्त स्टेल्ला क्यारीकाइडस ने मंकीपॉक्स से निपटने के वास्ते ‘‘ठोस और समन्वित कार्रवाई’’ करने का आह्वान किया। उन्होंने पत्र में कहा है, ‘‘यह आत्मसंतुष्टि का समय नहीं है और हमें इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना होगा।’’ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह मंकीपॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। स्टेल्ला ने कहा कि इस स्तर पर क्षेत्र की प्रार्थमिकताओं में मामलों की पहचान करना और संक्रमण के प्रसार को रोकना शामिल होना चाहिए।अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र के अनुसार, मई के बाद से 74 देशों में मंकीपॉक्स के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। अब तक, केवल अफ्रीका में मंकीपॉक्स से होने वाली मौतों की सूचना मिली है।

अमेरिकी सांसद प्रमिला को जान से मारने की

धमकी देने के संदेह में एक व्यक्ति गिरफ्तार

सिएटल । अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को जान से मारने की धमकी देने के संदेह में सिएटल के एक व्यक्ति को इस माह की शुरुआत में गिरफ्तार किया है। किंग काउंटी अभियोजन अटार्नी के कार्यालय ने कहा कि पुलिस द्वारा अतिरिक्त सबूत इकट्ठे करने के बाद ब्रेट फोरसेल पर आरोप लगाए गए हैं। देर रात जयपाल के सिएटल स्थित घर के बाहर अश्लील बातें करने और धमकियां देने के बाद फोरसेल को 9 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। जब अभियोजकों ने कहा कि हेट काइम के आरोप के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, तब फोरसेल को रिहा कर दिया गया। हालांकि मामले में अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी रहेगी। अभियोजकों ने कहा कि पुलिस ने बाद में पीछा करने के मामले पर संचालन लिया है।2016 में जयपाल अमेरिकी संसद के लिए चुनी गई पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी थीं। अपराधी के बारे में बताते हुए अभियोजकों ने कहा कि फोरसेल एक घातक हथियार से लैस था और जयपाल का पीछा उसने पद के कारण किया था। जानकारी के अनुसार, जयपाल ने देखा कि फोरसेल उनके घर के बाहर उनका नाम लेकर अभद्र बातें कर रहा है। इसके बाद उन्होंने 9 जुलाई को कॉल कर मामले को रिपोर्ट कराया। इस पर कार्रवाई करते हुए सिएटल पुलिस ने रात 11:25 बजे जयपाल के घर के बाहर से फोरसेल को गिरफ्तार किया।

रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के आरोप में कनाडा में दो लोग गिरफ्तार

टोरंटो । रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या के आरोप में दो लोगों को ब्रिटिश कोलंबिया के एट्सफोर्ड से गिरफ्तार किया है। मलिक को 1985 के एअर इंडिया कॉनिफ विमान आतंकवादी बम धमाके मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें 331 लोगों की जान गई थी। सिख समुदाय से संबंधित मलिक की 15 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कॉनिफ विमान बम धमाके के जुड़े मामले में मलिक और सह-आरोपी अजायब सिंह बागरी को 2005 में आरोपमुक्त कर दिया गया था। रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) ने सर्रे में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया के एट्सफोर्ड से 21 वर्षीय टैटर फॉक्स और न्यू वेस्टमिंस्टर के वैंकवर उपनगर से 23 वर्षीय जोस लोपेज को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी, पुलिस ने केवल इतना बताया कि मलिक की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी मनदीप मूकर ने कहा जांच और पुलिस की कुशलता से, इस हत्याकांड के संबंध में हमें दोनों संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस के पास इन दोनों के बारे में पहले से जानकारी थी। मलिक के बेटे जसप्रीत सिंह मलिक ने कहा कि उनके परिवार ने इस खबर पर झिली-जुली भावनाएं व्यक्त की हैं। जसप्रीत ने कहा जांच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमने एक महान व्यक्ति खो दिया है। जसप्रीत ने कहा कि पुलिस ने परिवार को कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है और वह इस विषय पर अटकलें नहीं लगाना चाहते कि उनके पिता को क्यों मारा गया।

जंग के बीच एक मैगजीन के लिए

जेलेंस्की ने पत्नी संग करायी फोटोशूट,

लोगों ने गैरजिम्मेदाराना बताया

कीव । युद्धग्रस्त यूक्रेन बीते 5 माह से जंग लड़ रहा है। रूस के साथ उसकी सेनाएं लड़ रही हैं। देश में चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने एक मैगजीन के लिए एक फोटोशूट करायी है। एक तस्वीर में जेलेंस्की और उनकी पत्नी एक दूसरे के करीब बैठे दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। मैगजीन ने यूक्रेन की पहली महिला की फोटो को बहादुरी की तस्वीर बताया है। एक अन्य फोटो में ओलेना सेना के क्षतिग्रस्त वाहन के साथ पोज दे रही है। वहीं एक फोटो में ओलेना एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पोज दे रही हैं। मैगजीन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ‘पत्रिका की विशेष डिजिटल कवर स्टोरी के लिए, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी पत्नी ने युद्ध के समय में जीवन, उनकी शादी और साझा इतिहास और यूक्रेन के भविष्य के सपनों के बारे में बात की।’ यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का फोटो शूट लोगों को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि जब आप एक एक्टर को अपना राष्ट्रपति चुन लेते हैं तो युद्ध के समय भी उसकी प्रायोरीटी अलग ही होती है। वहीं एक अमेरिकी ने लिखा कि जब यूएस 60 बिलियन डॉलर की मदद दे रहा है तब ये फोटोशूट करा रहे हैं। कई लोगों ने इसे बेहद गैरजिम्मेदाराना बताया। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया है। युद्ध को लगभग 155 दिन हो गए हैं। लगभग 7000 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूस का कब्जा है। डोनबास रीजन में रूस का हमला और भी तेज हो गया है। युद्ध के बीच एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसमें यूक्रेन ने तीन भारतीय लोगों को रूस का समर्थन करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया है।

म्यांमार के चार कार्यकर्ताओं को फांसी दिए

जाने की संरा सुरक्षा परिषद ने की कड़ी निंदा

जिनेवा । मानवाधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काफी सक्रिय है। परिषद ने म्यांमार द्वारा 4 राजनीतिक कैदियों को फांसी दिए जाने की सर्वसम्मति से निंदा की और उससे सभी प्रकार की हिसा को तत्काल रोकने तथा ‘मानवाधिकारों और कानून के राज का पूरा सम्मान’ करने का आह्वान किया। सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि चार राजनीतिक बंदियों को ऐसे वक्त में फांसी दी गई, जब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) ने सझा पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। परिषद के सदस्यों ने ‘म्यांमार के लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए पूर्ण समर्थन और म्यांमार की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा म्यांमार की एकता के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को भी दोहराया।’ गौरतलब है कि आसियान म्यांमा में शांति लाने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। म्यांमार में फरवरी 2021 में निर्वाचित सरकार का सेना द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद से व्यापक पैमाने पर अराजकता का माहौल है। आसियान ने इस सप्ताह दी गई फांसी की इस संज्ञा को ‘अत्याधिक निंदास्पक’ बताया और कहा कि इससे सैन्य नेतृत्व तथा विरोधियों के बीच संवाद के उसके प्रयासों को झटका लगा है। (जिन चार लोगों को सप्ताहांत फांसी दी गयी है उनमें ‘नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ के पूर्व सांसद, एक लोकतंत्र समर्थक और एक महिला की हत्या करने के दो आरोपी शामिल हैं, जिसे वे कथित तौर पर सेना की मुखबिर मानते थे।



कनाडा के सिटाडेले में कनाडा के गवर्नर जनरल के निवास पर एक स्वागत समारोह के दौरान पोप फ्रांसिस का स्वागत करते प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की गवर्नर जनरल मैरी साइमन।

तानाशाह नेता किम ने अमेरिका को दी चेतावनी

बोला- तनाव में परमाणु हथियार का प्रयोग करने से एक इंच नहीं कतराएगा उत्तर कोरिया

सियोल। (एजेंसी)।

दुनिया के नियमों को ताक पर रखने वाला उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन हमेशा अपनी मनमानी करता आया हैं। जहां पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम परमाणु शक्तियों का प्रयोग करने के नियम बना रही हैं वहीं वह लगातार परमाणु परीक्षण करके अपने देश के हथियारों को बढ़ाए जा रहा है। उत्तर कोरिया में लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं लेकिन उनकी चिंता छोड़कर किन दुनिया के ताकतवर देशों को धमकाने पर लगा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने चेतावनी दी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। राज्य मीडिया ने गुरुवार को कहा, क्योंकि उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उग्र बयानबाजी की, उनका कहना है कि कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध के कगार पर धकेल रहे हैं।

किम जोंग ने दी अमेरिका के खिलाफ परमाणु बम प्रयोग करने की धमकी

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के



साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। किम ने युद्ध की कगार पर धकेल रहे हैं। किम ने 1950-53 के कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। इस भाषण का उद्देश्य महामारी से संबधित आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे देश में आंतरिक एकता को बढ़ावा देना है। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया की धमकियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों

सहयोगी देश अपने सैन्य अभ्यास को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, जिसे उत्तर कोरिया आक्रमण के अभ्यास के तौर पर देखता है।

उत्तर कोरिया की परमाणु युद्ध क्षमता पूरी तरह तैयार

आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, किम ने बुधवार को भाषण में कहा, ‘‘हमारे सशस्त्र बल किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारे देश की परमाणु युद्ध क्षमता भी पूरी तरह तैयार है।’’ उन्होंने अमेरिका पर अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों को न्यायसंगत ठहराने के लिए उत्तर कोरिया की ‘‘खराब तस्वीर पेश करने’’ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास अमेरिका के ‘‘दोहरे मानदंड’’ के प्रतीक हैं, क्योंकि वह उत्तर कोरिया की नियमित सैन्य गतिविधियों को उकसावे या धमकियों के तौर पर दिखाता है। दरअसल, वह उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के संदर्भ में बात कर रहे थे। किम ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक यिओल को ‘‘उन्मादी’’ बताया, जो पूर्व के दक्षिण कोरियाई नेताओं से भी आगे निकल गए हैं और कहा कि यून की रूढ़िवादी सरकार का नेतृत्व ‘‘गुंडे’’ कर रहे हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आरोप,

न्यायपालिका उनकी सरकार के प्रति

दोहरा रवैया अपना रही

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को न्यायपालिका पर निशाना साधते हुए कुछ न्यायाधीशों पर उनकी गठबंधन सरकार के प्रति ‘‘दोहरा मापदंड’’ अपनाने का आरोप लगाया। उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) के नेता परवेज इलाही पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। इलाही (76) को अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी का समर्थन हासिल है। बुधवार तड़के उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसे प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शहबाज शरीफ ने यहां नेशनल असेंबली के सत्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं लेकिन नेशनल असेंबली में सच बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका न्याय को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगी और न्याय का मानक सभी के लिए समान होना चाहिए।

राष्ट्रपति बाइडन संक्रमण मुक्त,

‘कड़ा पृथक्कास’ समाप्त

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बुधवार को की गई जांच में कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त पाये गए हैं। इससे पहले मंगलवार रात की गई जांच में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी। बाइडन के डॉक्टर के हवाले से जारी पत्र में व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। संक्रमण मुक्त होने के बाद बाइडन ने ‘‘कड़ा पृथक्कास’’ समाप्त कर दिया है। 79 वर्षीय बाइडन पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। बाइडन ने अमेरिकियों से कहा, ‘‘कोविड गया नहीं है।’’ साथ ही लोगों से कहा कि कोविड-रोधी टीके की खुराक, बुस्तर खुराक और उपचार के जरिये गंभीर रूप से बीमार होने से बचा जा सकता है। संक्रमणमुक्त होने के बाद बाइडन ने बुधवार को व्हाइट हाउस के ‘रोज गार्डन’ में अपने संबोधन के दौरान जनता का आभार जताया और कहा, ‘‘अब मुझे ओवल कार्यालय वापस जाना निर्वहन कर रहे थे।



है।’’ इससे पहले, डॉ केविन ओकोनोर ने कहा कि राष्ट्रपति ने उपचार की अवधि पूरी कर ली है और उनको बुखार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बाइडन में कोविड-19 बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। व्हाइट हाउस के बयाना जन करने के कुछ देर बाद बाइडन ने ट्वीट किया, ‘‘ओवल (कार्यालय) में वापसी।’’ अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के साथ कोविड-19 रैपिड जांच वाली फोटो साझा करते हुए परिणाम ‘नेगेटिव’ आने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि बाइडन 21 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि, वह पृथक्कास के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

यूएसएआईडी की प्रशासक सामंथा पावर ने श्रीलंका की मदद

के लिए की भारत की सराहना, चीन को लेकर कही ये बात

न्यूयॉर्क (एजेंसी)।

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख सामंथा पावर ने श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत की सराहना की है। यूएसएआईडी प्रमुख इस समय भारत के दो दिवसीय दौर पर हैं। दिल्ली आईआईटी में एक कार्यक्रम में एक संबोधन में सामंथा पावर ने कहा कि चीन श्रीलंका के ‘सबसे बड़े लेनदारों’ में से एक बन गया है। यूएसआईडी की प्रशासक सामंथा पावर ने कहा कि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे श्रीलंका की भारत ने समय रहते मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत ने जहां उपयोग की एक महत्वपूर्ण सीरिज के साथ तेजी से प्रतिक्रिया दी सदस्य देशों ने दोहुक हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सभी देशों से इराक सरकार के साथ सक्रियता से सहयोग करने का अनुरोध किया।



आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि चीन श्रीलंका के सबसे बड़े लेनदारों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि चीन अक्सर दूसरे कर्ज देने वाले देशों या संस्थानों की तुलना में ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऋण सुविधा के तहत श्रीलंका को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। साथ ही श्रीलंका की गिरती इकोनॉमी को समर्थन देने के लिए कई अन्य तरह से मदद की पेशकश की है।

खोज ली चांद पर इंसानों के रहने लायक जगह, भविष्य में तैयार की जा सकती हैं मानव बस्तियां

वाशिंगटन (एजेंसी)।

बचपन में चांद पर रहने का सपना अब असल जिंदगी में संभव हो गया है। जी हां, अब इंसान चांद पर रह सकते हैं। बता दें कि चांद की सतह पर ऐसे गड्ढे मिले हैं जो कि इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही हैं। ये गड्ढे इंसानों के रहने के लिए उचित तापमान में पाए गए हैं। इन्हें नासा के लूनर रीकॉन्सेंस ऑर्बिटर की मदद से खोजा गया है। इन गड्ढों के अंदर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है जो कि इंसान के रहने के लिए सक्षम है। अगर भविष्य में इन गड्ढों के अंदर बस्तियां बसाने का सोचा जाए तो ऐसा संभव हो जाएगा।

इन गड्ढों की खोज की रिसर्च रिपोर्ट जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित की गई है। चांद पर रहने लायक

इन गड्ढों को देख वैज्ञानिक भी काफी हैरान हैं। चांद पर पाए गए ये गड्ढे चंद्रमा के अन्य इलाकों के गड्ढों से बिल्कुल अलग हैं। आपको बता दें कि चांद पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि धरती पर पानी उबल जाए और यहां एक दिन दो हफ्ते लंबा होता है। ऐसे में अगर इन गड्ढों का पता चलता है जो इंसानों के रहने के लायक है तो यह एक बड़ी बात है।

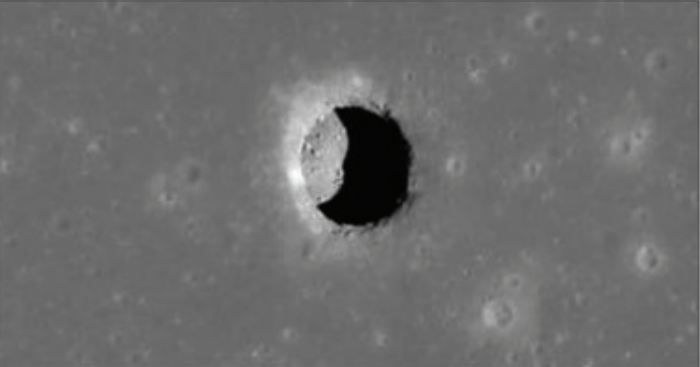
कहां मिले है यह गड्ढे

चांद पर इंसानों के रहने लायक यह गड्ढे मेयर ट्रांक्विलिटीटिस यानी सी ऑफ ट्रांक्विलिटी में मिले हैं और यह लगभग 328 फीट गहरे हैं। इनका तापमान चांद के अन्य गड्ढों के मुकाबले थोड़ा ही बदला हुआ है कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नासा के गोडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एलआरओ

प्रोजेक्ट की साइटिस्ट नोआ पेट्रो भी काफी हैरान हैं और उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर उनका तापमान लगातार स्थिर रहता है तो यहां इंसानों के लिए बस्तियां तैयार की जा सकती हैं। नोआ पेट्रो ने आगे बताया कि लूनर पिट्स की सबसे पहले खोज साल 2009 में की गई थी।

गड्ढे और पिट्स में क्या है अंतर

जानकारी के लिए बता दें कि पिट्स और गड्ढे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। गड्ढे जहां छिछले होते हैं वहीं पिट्स वर्टिकली सीधी गहराई वाले होते हैं। अगर इन्में जाने का रास्ता मिले तो अंदर एप्सोन्टॉटस अपने रहने की जगह का निर्माण कर सकते हैं जिससे सोलर रेडिएशन, घटते-बढ़ते तापमान और छोटे



उल्कापिंडों के टकराने का खतरा खत्म हो जाता है। ये चांद की सतह से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। भविष्य में इन पिट्स जैसे एप्सोन्टॉटस को रहना पड़ सकता है जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इंसानों के पूर्वजों का जन्म स्थल पहले

गुफा ही हुआ करता था। वहीं खाते और पीते थे। तो अगर सबकुछ सही रहा तो कुछ सालों में ही इंसान चांद पर रहने की गुफाओं में इंसानों को रहना पड़ सकता है जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इंसानों के पूर्वजों का जन्म स्थल पहले

जम्मू-कश्मीर में भीषण बारिश, रामबन के सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद

श्रीनगर। जम्मू क्षेत्र में गुरुवार को भारी बारिश के बाद अवानक बाढ़ आने और मिट्टी धंसने के कारण रामबन जिले में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि विनाब नदी में जल स्तर खतरे के स्तर 35 फुट से ऊपर चला गया है तथा प्राधिकारियों ने जल स्तर और बढ़ने की वेतानी दी है। मिट्टी धंसने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, इससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘ रामबन जिले में भारी बारिश के कारण जलाशयों का स्तर बढ़ने के कारण लोगों तथा बच्चों को उससे दूर रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने बताया कि कैफ़ेटरिया मूर और पटियाल इलाकों में पत्थर गिरे, जिससे मेहार पर कश्मीर को शेष देश से जोड़ने वाला यह राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। यातायात पुलिस के परामर्श के अनुसार, लोगों को मार्ग संबंधी पूर्ण जानकारी हासिल होने तक जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर यात्रा ना करने का सुझाव दिया गया है।

24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए, 44 लोगों की मौत

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,59,321 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 44 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,211 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,297 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.47 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 203.21 करोड़ खुरोंकें दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन को आय नहीं माना जा सकता, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

मद्रुरे। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन को किसी की आय नहीं माना जा सकता। यह पेंशन देश की आजादी की लड़ाई में योगदान को देखकर सम्मान स्वरूप दी जाती है। यह टिप्पणी कर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता महिला को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत दिगम्बर पिता की पेंशन के अलावा सरकारी कर्मचारी रही मां की फैमिली पेंशन भी दें। रिपोर्ट के अनुसार, मामला तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई का है। यहां एस.जीवालक्ष्मी नाम की महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके प्रशासन के फैमिली पेंशन देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी। अविवाहित जीवालक्ष्मी के पिता एसटी शिवास्वामी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन मिलती थी। जीवालक्ष्मी की मां एक निगम के प्राइमरी स्कूल में काम करती थीं। 1979 में मां की मृत्यु के बाद से उनकी फैमिली पेंशन भी पिता को मिलने लगी।

साल 2001 में शिवास्वामी का देहांत हुआ। उनकी कानूनी वारिस होने के नाते जीवालक्ष्मी को उनकी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलने लगी। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद न तब जीवालक्ष्मी ने और न ही उनके किसी भाई-बहन ने मां की फैमिली पेंशन निकाली। 2001 में सरकार ने आदेश निकाला कि फैमिली पेंशन 25 साल से ऊपर की अविवाहित बेटियों को भी मिलेगी, लेकिन शर्त ये लगाई कि उसकी महीने की आमदनी 2550 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में 2017 में, आमदनी की ये सीमा बढ़ाकर 7850 रुपये कर दी गई। 2017 में जीवालक्ष्मी ने अपनी मां की पेंशन लेने के लिए आवेदन दिया, जिसे मंजुरी दे दी गई। हालांकि एक साल बाद ही अधिकारियों ने ये कहकर पेंशन बंद कर दी कि वह पेंशन पाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन मिल रही है। अधिकारियों के आदेश को जीवालक्ष्मी ने मद्रास हाईकोर्ट में 2020 में चुनौती दी। वहीं मामले में कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी गई कि जीवालक्ष्मी को सेनानी पेंशन के तौर पर 13390 रुपये मिल रहे हैं, इस तरह वह मां की फैमिली पेंशन के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी महीने की आमदनी निर्धारित सीमा से ज्यादा है। इसपर हाईकोर्ट के जस्टिस बी पुगलेंथी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट भी अपने पहले के फैसलों में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के बलिदान और योगदान को देखते हुए दी जाती है। यह एक सांकेतिक सम्मान की तरह है। इसके बाद इस पेंशन को इनकम के दायरे में नहीं माना जा सकता।

दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ एकजुट
हैदराबाद। दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 सीटें हैं। इनमें से कर्नाटक की 25 तथा 4 अन्य राज्यों में लोकसभा की सीटें भाजपा के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय दलों के बीच सेंध लगाने का काम कर रही है। इससे दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत की संस्कृति और प्रत्येक राज्य का ताना-बाना भाषाई प्रसक्तियें बनी रहे। इसके लिए क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दक्षिण भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर,भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिंदी भाषा और हिंदुत्व को नए नजरिए को थोपने का विरोध दक्षिण भारत के राज्य करने लगे हैं। पिछले कुछ माह में क्षेत्रीय दलों के खिलाफ जिस तरह से तोड़फोड़ का अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उससे दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल सतर्क हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के पूर्व दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बन रहा है। वह आश्चर्यजनक करने वाला है।

अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी, दूसरे घर में भी मिला अकूत खजाना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। अर्पिता मुखर्जी के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कोलकाता के आसपास 3 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित एक और फ्लैट पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की इस छापेमारी में करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो के आसपास सोना बरामद हुआ है। कैश की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि ईडी को इसे गिनने में 10 घंटे का समय लग गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अर्पिता ने यह सारा पैसा टॉयलेट में छिपा रखा था। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में टीयर भत्ती घोटाले में कार्यवाही कर रही है। इसी सिलसिले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब यह घोटाला हुआ, उस समय पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षामंत्री थे। इससे पहले ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से करीब 21 करोड़ और कीमती सामान बरामद किए थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। यही कारण है कि अब पार्थ चटर्जी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस में भी पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग उठने लगी है। ईडी पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को फ्लैट के दरवाजे तोड़ने पड़े। मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान ईडी को कोलकाता के आसपास की अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि हमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में दो में से एक फ्लैट में बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। हमने रुपयेों की गिनती के लिए तीन मशीनें मंगवाई हैं, ताकि पता चले कि वास्तव में कितनी राशि है। उन्होंने बताया कि फ्लैटों की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं।

मुझसे बात मत करो, संसद में स्मृति ईरानी पर भड़कीं सोनिया गांधी दोनों में हुई तीखी बहस

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

भाजपा की ओर से राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया गया। इसके बाद अब सदन से बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की तीखी बहस हुई है। दरअसल सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने के बाद सोनिया गांधी जब बाहर निकल रही थीं तो उन्हें देखकर भाजपा के सांसद नारेबाजी करने लगे। इस बीच सोनिया गांधी भाजपा की सांसद रमा देवी के पास आई और उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने बीच में दखल देने की कोशिश की, जिस पर सोनिया गांधी भड़क गईं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी ने Don't talk to me कहा, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने भी कुछ कहा और दोनों के बीच करीब दो मिनट तक तीखी बहस चली। साफ है कि संसद में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच कड़वाहट बढ़ गई है और नेताओं के आपसी रिश्तों में भी खटास देखने को मिल रही है। बता दें कि स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर संसद में भी आक्रामक थीं। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी की अनुमति



से ही अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा बयान दिया है, इसलिए खुद सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर कहा, ‘हमारे कुछ लोकसभा सांसदों को खतरा महसूस हुआ जब सोनिया गांधी हमारी वरिष्ठ नेता रमा देवी के पास यह जानने के लिए आईं कि क्या हो रहा था। इस दौरान हमारा एक

सदस्य वहां पहुंचा और सोनिया गांधी ने कहा ‘मुझसे बात मत करो। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया। लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं।

बच्ची बोली आप मोदी जी हैं और लोकसभा में काम करते हैं, जवाब सुनकर खूब हंसे पीएम मोदी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

पीएम मोदी को बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चों के सामने वह बहुत अलग अंदाज में पेश आते हैं। ऐसा ही एक वाक्यका पीएम मोदी के ऑफिस का है, जब भाजपा सांसद की पांच वर्षीय बेटी से पीएम मोदी ने पूछा कि क्या आप और मुझे जानती हैं? बच्ची ने कहा मैं आपको जानती हूं, आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। यह जवाब सुनकर से पीएम मोदी सहित वहां बैठा पूरा स्टाफ हंस पड़ा। बच्ची की मासूमियत से पीएम मोदी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस बच्ची से देर तक बात की और जाते समय एक चाकलेट भी दी।

दरअसल मामला यह है कि बुधवार को भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया की 5 साल की बेटी से पीएम मोदी ने बातचीत की। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद फिरोजिया संसद में अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। इस दौरान उनकी 5 साल की बच्ची अहाना भी उनके साथ थी। पीएम मोदी ने अहाना फिरोजिया से पूछा कि क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? तो 5 वर्षीय बच्ची ने जवाब दिया



हां, मुझे पता है आप मोदी जी हैं। आप टीवी पर रोज आते हैं। इसके बाद, पीएम ने बच्ची से पूछा क्या आप जानती हैं कि मैं क्या करता हूं? इस पर अहाना ने तुरंत जवाब दिया आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े और हंसते हुए पीएम मोदी ने लड़की के कमरे से निकलने से पहले उसे चांकलेट दी।

अहाना के पिता हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तुत एक चुनौती लेने के बाद अपना वजन कम करने के लिए सुविधियों में आए थे।

पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए फिरोजिया ने कहा आज एक

अविस्मरणीय दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के सबसे सफल और सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सौभाग्य मिला। उनका आशीर्वाद और जनता की निस्वार्थ सेवा का मंत्र प्राप्त हुआ। फिरोजिया ने कहा मैं भाग्यशाली हूं कि देश को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे मेहनती, ईमानदार, निस्वार्थ और बलिदानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुझे जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। आज मेरी दोनों बेटियां, छोटी लड़की अहाना और बड़ी लड़की प्रियांशी प्रधानमंत्री से सीधे मिलने और उनका स्नेह पाने से खुश और अभिभूत हैं।

मंकीपॉक्स संक्रमण के 95 प्रतिशत मामलों का कारण यौन संबंध

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दुनिया भर में मंकीपॉक्स के बढ़ते संक्रमण के बीच रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। शोध में कहा गया है कि मंकीपॉक्स से संक्रमित 98 प्रतिशत पुरुष थे, और इसमें से ज्यादातर, पुरुषों (एमएसएम) के साथ यौन संबंध रखते थे। इसके साथ ही 41 प्रतिशत रोगियों को एचआईवी संक्रमण था। रिसर्च में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्तियों की औसत आयु 38 वर्ष थी और संदेह है कि संक्रमण के 95 प्रतिशत मामलों का कारण यौन संबंध है।

रिसर्च में आंशिक जाहिर की गई है कि मंकीपॉक्स संक्रमण यौन संबंधों से फैल रहा है। रिसर्च में 27 अप्रैल से 24 जून के बीच 16 देशों में 43 जगहों पर 528 संक्रमितों का ऑब्जर्वेशन किया गया।

हालांकि इनमें से किसी की मौत नहीं हुई है। इनमें सिर्फ 13 प्रतिशत रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता लगी। अभी तक 74 देशों में मंकीपॉक्स के लगभग 18,000 मामलों मामले सामने आए हैं। काफलों की समीक्षा से साफ होता है, कि संक्रमित लोगों में से 1 से 3 प्रतिशत मरीजों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई और मृत्यु दर 3 से 6 प्रतिशत है। वहीं भारत में मंकीपॉक्स संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट्स ने एचआईवी/एड्स रोकथाम नेटवर्क और इस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ के माध्यम से निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

राष्ट्रपति का अपमान: अधीर रंजन पर केंद्रीय मंत्रियों ने बोला चौतरफा हमला

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा ‘राष्ट्रपत्नी’ कहे जाने पर गुरुवार को सियासी हंगामा हो गया। जहां बीजेपी के तमाम नेताओं ने अधीर रंजन पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाकर तीखे हमले किए। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी लगातार अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इधर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ‘वह मानते हैं कि उनसे चुक हुई है। गलती से उनके मुंह से ये शब्द निकल गया है। कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। जरूरत पड़ी तब मैं राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा।

कांग्रेस नेता चौधरी पर हमला बोलकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि ‘लोकसभा में विपक्ष के नेता का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का अपमान करना था, जो एक स्व-निर्मित महिला हैं, एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा है। राष्ट्रपती’ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होता है। राष्ट्रपति शब्द पुरुष और महिलाओं दोनों

के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता है। यह एक सामान्य ज्ञान है।

वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनीं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहाज कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रपति के अपमान को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे जनजातीय समाज का बार-बार अपमान करती रही है। आज कांग्रेस की अध्यक्ष कहती हैं कि अधीर रंजन ने माफी मांगी, लेकिन अधीर रंजन कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं?

वहीं बीजेपी सांसद रमा देवी ने रंजन की टिप्पणी को लेकर कहा कि राष्ट्र इस बर्दाश्त नहीं करेगा। महिलाओं के रूप में हम इस बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति होने पर शर्म महसूस करने के लिए हमें (कांग्रेस नेता) पर शर्म आती है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये (अधीर चौधरी की ‘राष्ट्रपत्नी’

367 जगहों पर स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली । महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 367 जगहों पर स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल आरक्षण की अनुमति मिलने से पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने 367 जगहों के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद अब यहां बिना आरक्षण के ही चुनाव होना। कोर्ट ने कहा कि उन सीटों के लिए नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया, तब ये कोर्ट की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगा दी। दरअसल आयोग ने आरक्षण देने के लिए दोबारा अधिसूचना जारी करने का आदेश जारी किया था। जिसे शीघ्र अदालत ने ने गलत माना, अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग उन चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। बता दें कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) और सभी राज्य प्राधिकरणों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।

एकनाथ शिंदे के समूह वाली शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ेंगे औरंगाबाद निकाय चुनाव



औरंगाबाद। (एजेंसी)।

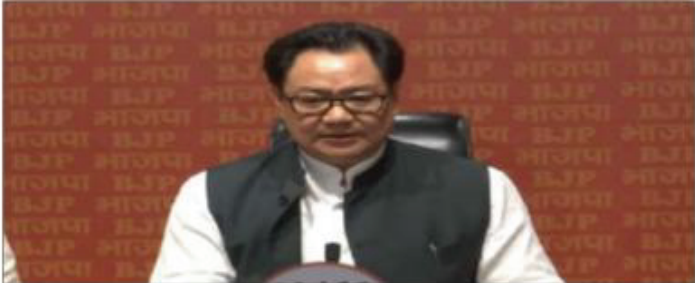
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का बागी समूह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन बनकर औरंगाबाद नगर निगम (एमएससी) का चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना के बागी समूह के एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दरअसल, जल्द ही एएमसी चुनाव होने वाले हैं और तारीखों की घोषणा की जानी बाकी है। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन तीन दशकों से अधिक समय तक नगर निकाय में सत्ता में रह चुका है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली

शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर राज्य में महा विकास आघाड़ी सरकार का गठन किया था। इसके बाद एएमसी के उपमहापौर विजय औतादे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। औतादे भाजपा के नेता हैं। एकनाथ शिंदे के समूह वाली शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जांजल ने पीटीआई-से कहा, ‘‘अब शिंदे समूह और भाजपा औरंगाबाद नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ेंगे। इस पर शुरूआती चर्चा पहले ही हो चुकी है।’’ उन्होंने दावा किया कि औरंगाबाद का विकास तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने शहर के लिए धनराशि देना शुरू किया था।

वाली टिप्पणी) दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये सर्वोच्च पद पर बैठे देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है।

उधर चौधरी ने संसद भवन परिसर में कहा कि मैं जानता हूं कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हों, हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये चुक हुई है लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैंज अगर जरूरत पड़ी तब मैं राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा। मैं बार-बार कह रहा हूं कि मुझसे चुक हुई है लेकिन ये सभी मुद्दे को चपका रहे हैं। मुझे बोलाने का मौका देना चाहिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च स्थान पर हैं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कहुं।

इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर के बयान पर हंगामे के बीच कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी उनका बचाव करती दिखीं। सोनिया ने कहा कि वह (अधीर) पहले ही माफी मांग चुके हैं। संसद भवन परिसर में जब सोनिया गांधी से पूछा गया कि क्या वह अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने के लिए कहींगी तब उन्होंने कहा, ‘वह पहले ही माफी मांग चुके हैं।



तरह से अपमान करने वालों से हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा का ध्यान गलती स्वीकारो...ये चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के बारे में क्या कहते हैं? शशि थरूर की पत्नी और रेणुका चौधरी के बारे में क्या कहा? मैंने राष्ट्रपति से समय मांगा, मैं उनसे बात कर माफी मांगूंगा।

अधीर रंजन ने मांगी माफी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक बयान मामले में अधीर रंजन ने